

†EXPORTS OF SEA FOOD

355. DR. (MRS.) MANGLADEVI TALWAR : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether sea food exports during 1968-69 have hit a new high ;

(b) if so, the extent of exports in terms of quantity and the foreign exchange obtained thereby during that year ;

(c) how it compares with the respective figures for the preceding three years ; and

(d) the targets of sea food exports, itemwise fixed for the year 1969-70 and the amount of foreign exchange expected therefrom ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) to (c) Yes, Sir. The comparative statement of exports during 1965-66, 1966-67, 1967-68 and 1968-69 is as follows :—

Year	Quantity (Tonnes)	Value (Rs. crores)
1965-66 . .	15295	7.06
1966-67 . .	21116	17.37
1967-68 . .	21907	19.72
1968-69 . .	26811	24.70

(d) No official target has been fixed for the year 1969-70 for the exports of sea-foods.

†EXHIBITION OF TAMIL FILMS IN
CEYLON

372. SHRI M. SRINIVASA REDDY :
SHRI Y. ADINARAYANA
REDDY :

SHRI S. A. KHAJA MOHI-
DEEN :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Times of India', dated June 7, 1969 (Delhi Edition) to the effect that Tamil films are being banned in Ceylon, and

(b) if so, whether Government propose to discuss this matter with the Government of Ceylon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) and (b) Government have seen the news item in question. Ceylon has not imposed a ban, as such on Tamil films. The import quota for Indian films has however been reduced. The matter has been taken up with the Government of Ceylon.

CALLING ATTENTION TO A
MATTER OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE

GRANT OF SCHOLARSHIPS OUT OF CENTRAL GRANTS TO STUDENTS BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के मेट्रिक के बाद कालेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को केन्द्रीय अनुदानों में से छात्रवृत्तियाँ दिये जाने के संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किये गये हाल के आदेशों की ओर विधि तथा समाज कल्याण मंत्री का ध्यान दिला रहा हूँ।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. GOVINDA MENON) : Sir, the main points in the recent orders are :

(1) Students who enter a course after they have completed the age of 30 will not be eligible for new scholarships.

(2) The means test which already existed for scheduled castes has been extended to scheduled tribes. Previously there were 11 slabs of income specified in the orders and now it has been simplified to two slabs. Those whose income does not exceed Rs. 360 per mensem will get full scholarships and those whose income exceeds Rs. 360 but not Rs. 500 per mensem will be paid a block grant for their tuition fees and books etc. and half maintenance charges.

†Transferred from the 25th July, 1969.

(3) A merit test of a minimum of 45% marks has been introduced for post-Graduate scholarship.

These changes have been effected with a view to enhance substantially the rate of scholarship to the students. The Object is to distribute the available resources for payment of scholarships in the most fruitful and effective manner. The total grant available for scholarships has not been reduced. This matter is now being considered by the Parliamentary Committee for the welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes and Government await their report on this matter and would be willing to reconsider the whole question in the light of the reports received.

श्री मानसिंह वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इससे कि मैं प्रश्न करूँ मैं क्षमा चाहूँगा कि दो मिनट इसकी पृष्ठभूमि के लिये लेना चाहूँगा। अब तब जितनी भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती थीं, अर्थात् मैट्रिक पास करने के पश्चात् एम० ए० तक या एम० ए० के पश्चात् भी जितनी टेक्निकल एजुकेशन है उस सब में, सब छात्रों को दी जाती थीं, कोई नम्बर नहीं था, कोई संख्या नहीं थी, सब को ही केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्तियाँ मिलती थीं, परन्तु अब जो नया आदेश जारी किया गया है उसमें कुछ इस प्रकार की शर्तें लगा दी गई हैं जैसा कि मंत्र महोदय ने अभी बतलाया कि राज्य सरकारों को यह आदेश दिये गये हैं कि वह अपने नान-प्लाड बजट में से ये छात्रवृत्तियाँ देंगे और उसके बाद यदि कमी पड़ेगी तो केन्द्रीय सरकार उसे पूरा करेगी और उसके लिये भी जो शर्तें अब लगाई हैं वे शर्तें पहले नहीं थीं, जिनका वर्णन मैं संक्षेप में करना चाहूँगा।

पहले शेड्यूल्ड कास्ट के लिये आय का किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं था। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिला करता था। उनके लिये आमदनी का कोई प्रश्न नहीं था। दूसरा यह जो है कि 45 परसेंट मार्कस् वह लेगा तो उस बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी, अब तक इस प्रकार का नहीं था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस प्रकार को जो सहायता दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह केवल उनकी निर्धनता, गरीबी, उनके पिछड़ेपन, को ही देख कर दी जा रहा है। एक बच्चा जो कि झोपड़ी में रह रही है, जिसका पारिवारिक जीवन इतना पिछड़ा हुआ है, उसके लिये इतने साधन नहीं हैं कि वह दूसरे बच्चों के मुकामिले में इतने मार्कस् ला सके। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुये आज तक यह प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ था, किन्तु अब जो नई शर्तें लगाई गई हैं उसमें उसको 45 परसेंट मार्कस् लाना होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : That is only for post-graduates.

SHRI J. P. YADAV (Bihar) : Post-matric, not post graduate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : 45% is for post-graduate.

श्री मानसिंह वर्मा : जी हाँ पोस्ट ग्रेजुएट में एम० ए० भी आ गया।

दूसरी बात यह है कि अब तक जिनके अभिभावकों की, गार्डियंस की इंकम 500 रु० होती थी, या 500 रु० से ऊपर होती थी, उनको आधी छात्रवृत्ति मिलती थी किन्तु अब वह सीमा घटा कर 360 रु० से 500 रु० तक कर दी गई है।

श्रीमन्, इन शर्तों के कारण से तमाम प्रदेशों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं और इस प्रकार के पत्र हमको प्राप्त हो रहे हैं कि तमाम देश के अन्दर एक . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : It appears that you do not know the exact position. The exact position is that those whose income does not exceed Rs. 360 per month will get full scholarship. There is no change and those whose income exceeds Rs. 360 but less than Rs. 500 will be paid block grant for their tuition fees.

श्री मानसिंह वर्मा : वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 500 की जो लिमिट थी उसको 360 की लिमिट पर ले आये हैं। तो इन शर्तों के कारण एक गम्भीर स्थिति हो रही है। अब तक जितना काम हरिजनोत्थान का किया गया है उस सब में यदि कोई काम हुआ था तो वह शिक्षा के क्षेत्र में ही हुआ था।

और यह देखिये, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पूज्य बापू जी जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके सुधार के लिये संघर्ष करने में लगाया है, उनकी जन्म शताब्दी के वर्ष में यह इनाम आज दलित वर्ग को दिया गया है। आज चारों तरफ से यह समाचार आ रहे हैं कि बच्चे अब पढ़ नहीं पायेंगे। मैं जानता हूँ और मुझे अपने प्रदेश में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशल ऑफिसर बन कर काम करने का मौका मिला है, कि यदि इस प्रकार की सरकार की ओर से अनुदान या सहायता न होती तो मैं कह सकता हूँ कि इतने बच्चे हमारे पढ़ नहीं सकते थे। मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अब तक जो सहुलियतें दी जा रही थीं, उनको बिड़ड़ा करने का आधार क्या है? क्या किसी प्रकार का क्या रिज्यू कर लिया गया है क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि अब तक जो रिपोर्ट आई हैं, समय समय पर क्वेश्चन आते रहे हैं, प्रतिवेदन है उन सब में एक मत से यह बात स्वीकार की गई है कि अभी तक उनके सुधार में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है, जितना कार्य होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है। अभी कल ही इन तमाम बातों को लेकर लगभग 106 संसद सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री जी को स्मरण पत्र दिया है और जब वह स्मरणपत्र देने लगे तो श्रीमान्, प्रधान मंत्री जी ने आश्चर्य प्रकट किया, कि मैं नहीं समझता कि यह कैसे आदेश हो गये और किस प्रकार से ऐसा हो गया, मैं इसको देखूँगी। उन्होंने इसको पुनर्विचार करने का आश्वासन भी दिया। तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि इसका आधार क्या है, क्या समझ कर ऐसा किया गया है? क्या राज्य सरकारों से इसके लिये परामर्श कर लिया गया था और यदि

परामर्श कर लिया गया था तो क्या राज्य सरकार इसके लिये तैयार हो गयी कि हम अपने नौन प्लान बजट से यह छात्रवृत्तियाँ देंगे? इन प्रश्नों का उत्तर मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा।

SHRI P. GOVINDA MENON : Mr. Vice-Chairman, as I submitted, there is a Committee of this Parliament which looks into the question of the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and that Committee is looking into this matter. If they advise me that this should be changed and I should revert to the old state of affairs, I have absolutely no objection to review these things.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : He wants to know what is the basis for the change.

SHRI P. GOVINDA MENON : The basis for the change was this, Sir. The money is limited. A demand for enhancement of the rates of scholarship was there, and the demand for enhancement of the rates of scholarship was considered to be a good demand, and therefore we wanted to enhance the rate of scholarship. And with the amount available . . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) Mr. Vice-Chairman, you asked him a legitimate question. He should tell us what would have been the financial implication. Suppose, without changing it you had met the increased demand, what extra money would have been required, so that we can judge it on that basis?

SHRI P. GOVINDA MENON : Sir, the moneys that have been spent for the last few years are with me. The latest amount is Rs. 6.55 lakhs and it would have been much more, and I have already moved the Finance Ministry to give more grants. And I am also aware of the representations made by the hon. Members to the Prime Minister. (Interruptions) It is done for that purpose. Sir, I assure the House that in view of the discontent over the new changes which have been proposed, I am prepared to reconsider them.

SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat) : May I know, Sir, . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : There are other names in the list. Mr. Sundar Singh Bhandari.

[Shri P. Govinda Menon]

The proposal is there to enhance the scholarship to those who are undergoing technical courses by 100 per cent. and by 50 per cent. in the case of academic courses. This matter also is awaiting the clearance by Finance. The hon. Member requested me to study the whole matter. I agree to do so.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : I raised the question about 45 per cent.

SHRI P. GOVINDA MENON : On that matter I have no figures with me now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : I do not think that any further questions are necessary because he is staying the order and the status quo will remain. Next in the list is the name of Shrimati Sarla Bhadauria.

श्रीमती सरला भवौरिया (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य से चिंता में पड़ गई थी लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि हम सारा आदेश वापस ले लेंगे और हम उनको तरक्की की पूरी सुविधा देंगे। मेरा तो यह विश्वास है कि कुछ विशेष अवसर के द्वारा ही उनमें तरक्की लायी जा सकती है। जो आंकड़े बताये हैं मंत्री महोदय ने कि साढ़े छ लाख २० दे चुके हैं, तो मिक कोट से जो अनुदान दिया गया वह कम ही है। मुझे यह कहना है कि मंत्री महोदय राज्य सरकारों का बहाना लेकर या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का बहाना लेकर कहीं फिर गुमराह न हो जाये। अभी तक इतने दिनों का जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार सरकार जिस बात को अभी तक कहते आई है वाद में उसको बदल देगी। मुझे आशका है कहीं ऐसा ही न हो जाये अभी यहा फ्लोर में कहने के बाद, कहीं कमेटी में बैठने के बाद, वह बदल न जाये। दूसरी बात मे यह कहना चाहती हूं कि अगर खजाने में रुपयों की कमी है, पैसों की कमी है केन्द्रीय सरकार के पास, तो यह जो संसद् सदस्यों का वेतन भत्ता बढ़ाया जा रहा है उसे बंद किया जाय और मंत्रियों को विलासता को कम किया जाय। हमें देश के हित को सामने रखना है और समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें सब के बराबर में लाना है। यह सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है, जो इस देश

में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती है, उसने इन पिछड़े हुए लोगों को जो भी अधिक से अधिक देने का वचन किया उससे भी अधिक अनुदान उनको बेह्तरी के लिए दिया जाना चाहिये। इस तरह के काम में कोई भी कमी किसी तरह की करना अनुचित है।

मैं तो यह कहना चाहती हू कि वास्तव में एक ही उदाहरण उनकी तरक्की का हम देश के सामने ला सकते हैं अगर हम उनमें से किसी को राजदूत बनाकर या वैज्ञानिक बनाकर दिखावाये। हमने इतने दिनों तक इन लोगों को विशेष सुविधा दी है, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि हरिजनों और आदिम जातियों में से अभी तक एक भी वैज्ञानिक बड़ा वैज्ञानिक नहीं निकल पाया है। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि इतनी विशेष सुविधा देकर आपने इन लोगों की क्या तरक्की की है। आप इन लोगों का सामाजिक स्तर उठाइये, सुसंस्कृत बनाइये और सुशिक्षित बनाइये ताकि वे आगे चलकर जिम्मेदारों के पदों पर पहुंच सकें। यह बात मैं केन्द्रीय सरकार से चाहती हूं।

SHRI P. GOVINDA MENON : The hon. Member wanted me to say once again that I won't change my promise after going out of this House. Suppose I repeat my promise once again; then also I can change it. I made it on the floor of the House on the representation made by Mr. Bhandari that this Order should be stayed until after the matter is fully discussed and reported upon.

I committed a mistake in my previous answer; I said six lakhs but it is six crores.

SHRI KOTA PUNNAIAH (Andhra Pradesh) : Sir, let me offer my thanks to the hon. Minister first for staying this circular. It is deplorable that the Deputy Minister once answered a question whether these scholarships provided a means of livelihood for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That hurt many people and created apprehensions about this circular. I want to know specifically whether this circular would not arrest the progress of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes when they have not made adequate progress up till now. I want specific answers to these two points that I have raised.

SHRI P. GOVINDA MENON : Sir, that is a matter of opinion but since the opinion of friends in this House is that this should be stayed I am staying that. So that does not further arise.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान्, इस सवध मे जब मंत्री जी विचार विनिमय कर रहे है तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी अपने सम्मुख शुरू से जब से यह समाज कल्याण की योजना चली है उसको अपने सामने रखें। जब यह योजना शुरू शुरू में चली थी तो उस समय यह योजना थी कि इन लोगों को पैसे की गारन्टी दी जानी चाहिये। सामान्य रूप से यह योजना थी कि जितने भी हरिजन विद्यार्थी है, उनको स्कालरशिप मिलेगा, उनको फ्रीशिप मिलेगी और उनको पढ़ने के संबंध में सारी सहुलियतें मिलेगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश में यह मांग थी कि इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किया जाना चाहिये। अगर हम विद्यार्थियों को फ्रीशिप करते हैं और उनके पास खाने को न हो तो वे पढ़ने कहा जायेगे? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि पहले उनके लिए खाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। तो मैं यह चाहता हू कि पहले तो सरकार यह बतलाये कि यह जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन कौन मेम्बर है

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : यह चीज तो रिकार्ड में अवैलेबिल है।

श्री राजनारायण : अगर माननीय मंत्री जी यहां पर बतला दें तो इसमें उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि इस कमेटी में कौन कौन मेम्बर हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : इसमें दोनों हाउसों के मेम्बर हैं।

श्री राजनारायण : इससे मैं यह समझ पाता हू कि जो लोग इसमें है वे सही तौर पर हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों को उठाना चाहते है या नहीं और उन्हें विशेष सुविधा देकर दूसरे लोगों के मुकाबले में लाना चाहते हैं या नहीं। यह बात

ठीक है कि आप स्टे आर्डर कर देंगे, लेकिन इससे होगा क्या? मैं यह कहना चाहता हू कि हरिजनों की पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों को भोजन दिलाने के लिए आज यह सरकार विचार करने जा रही है या नहीं? अगर सरकार उनकी पढ़ाई और भोजन का प्रबन्ध नहीं करती है तो उनके लिए आर्थिक समस्या खड़ी हो जायेगी जिसकी वजह से वे उन्नति नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने जो नया आर्डर निकाला है उसको आप निकाल दोजिये।

एक बात मैं और जरूरी कहना चाहता हू कि यह जो परसेन्टेज की बात है, उन्हें इसेटिव देने की बात है, यह उनको परिश्रम करने के लिए प्रेरणा दे सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी 50 परसेंट मार्क पाये या फर्स्ट डिवीजन पाये तो उसको कोई स्पेशियल सहुलियत दी जानी चाहिये। अगर आप ऐसी कोई चीज अलग से करते है तो मैं उसको मान सकता हू। अगर यह जो 60, 50 प्रतिशत मार्क पाये उसे कुछ दिया जाय या न दिया जाय, यह बात में गलत मानता हू। खाना और फ्रीशिप तो उन्हें मिलेगा ही लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई लड़का अच्छे नम्बर लाता है तो उसको अतिरिक्त सहायता या सहुलियत दी जानी चाहिये; आप इस चीज के लिए कुछ अतिरिक्त नम्बर रख सकते हैं कि इतने नम्बर पाने वाले लड़के को यह यह सहुलियत मिलेगी। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो इससे हरिजन लड़कों को अपनी प्रतिभा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह तो दृष्टि का सवाल है।

मैं माननीय मंत्री जी से अदब के साथ कहना चाहता हू कि यह प्रश्न टेक्नलिटी का नहीं है, यह प्रश्न केवल सरकारी खजाने का नहीं है। यह प्रश्न तो केवल दृष्टि का है। अगर हमारी दृष्टि विकास की होगी तो हम इन लोगों का विकास कर सकते हैं। जिस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में लोगों का विकास हुआ है क्या इसी तरह से इन लोगों का भी आगे विकास होगा। तो

[श्री राजनारायण]

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन लोगों का किस दृष्टि से विकास किया जायेगा। आज तक पंचवर्षीय योजनाओं से जिस समाज का विकास हुआ है क्या उन्हीं का आगे भी विकास होगा या जो समाज के निचले वर्ग हैं, जो दबे पड़े हुए हैं उनका भी विकास होगा। तो यह दृष्टि का सवाल है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस दृष्टि से इस चीज को देखेगी कि जो समाज के अन्दर निचले हिस्से के लोग हैं उनका उत्थान किया जायेगा। क्या उन्हें विशेष सुविधा देकर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें देश की अन्य जनता के मुकाबले खड़ा करने के लिए हर तरह की सहुलियत देगी या नहीं? अगर सरकार की इस तरह की दृष्टि नहीं है तो चाहे वे कितने ही स्कूल खोल दे, कितनी और चीज उनके लिए कर दे, उनमें अनेक पेचकशी निकल सकती हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Mr. Rajnarain, I have already pointed out that this is not a debate. This is calling attention. A statement has been made by the Minister. If you want any clarification about it, please seek it.

श्री राजनारायण : वही तो श्रीमन्, मैं कह रहा हूँ। क्या सरकार की दृष्टि इस तरह की है कि जो सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए लोग हैं उनका सामाजिक स्तर आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम उनको शिक्षित किया जायेगा और उनको शिक्षित करने के लिए किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरह की दृष्टि अपनाये मगर मैं देखता हूँ कि वह इस तरह की दृष्टि अपनाने के लिए तैयार नहीं है।

SHRI P. GOVINDA MENON : I do not want to enter issue with the hon. Member on the generalisations which he made with respect to the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He raised a pointed question regarding feeding. I understand that Harijan students living in hostels are already entitled to higher rates of scholarship. With respect to the other matters I very respectfully

submit to the House that having constituted a Committee of both Houses of Parliament and having promised to the House that we will abide by the advice of this Committee and having categorically stated that till their advice comes the new order will be stayed and the old order will continue to prevail, I now say further that it shall now be my attempt to see that scholarships, post-matric and otherwise, to the Harijan and Gijian students are enhanced to the possible extent to which finances will permit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Just one minute. I have still got ten names before me and if we go on the way we have been proceeding it will take a long time. If hon. Members have still clarifications to seek, I will call out their names one by one and they can put a short question. Then we can finish this by one 'o' clock but if hon. Members go on expressing their opinion it will not be possible to finish this.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारे सवाल का क्या हुआ ?

सेवानियोजन तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जय सुख लाल हाथी) : वह हो गया। उसको देखेंगे।

SHRI P. C. MITRA (Bihar) : I would like to know whether it is not a fact that the Harijan students used to get free tuition irrespective of their income and, if so, why is this new procedure of granting them tuition fee only if their income is above or below Rs. 360 or Rs. 500 thought of?

SHRI P. GOVINDA MENON : The question and the answer relate to post-matric matters. Now, with respect to those below the matriculation classes, the freeship arrangements continue.

SHRI B. T. KEMPARAJ (Myore) : I want to know from the Minister whether there is any income slab fixed in the States of Kerala, Andhra and Tamil Nadu in the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students for the payment of grants sanctioned for giving educational facilities to them. My second question is this. The hon. Minister has used the word "discontent" twice. It is due to the discontent of the majority of Members that he is issuing the present circular. Therefore, I request him, let it not be with discontent, but with pleasure. He may see that the circular is clarified and the benefits extended without any income limit.

SHRI P. GOVINDA MENON : I used the word "discontent" in the sense of disagreement and because there is disagreement with respect to the new order, I have, with great pleasure, stayed the operation of the new order.

SHRI B. T. KEAPARAJ : What about the first part of my question ?

SHRI P. GOVINDA MENON : I want notice.

THE VICE-CHANCELLOR (SHRI M. P. BHARGAVA) : He has no information.

SHRI K. S. CHAVDA : In view of the fact that the States have never used fully the fifty per cent grant given to them for pre-matric education for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and in view of the fact that the percentage of literacy among them is not more 10.27 and 8.51 respectively, may I know whether Government will introduce the pre-matric scholarship scheme like post-matric scholarship scheme for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to promote education among them and bring them on par with the rest of the population of our country? Secondly, with regard to regulation 6 (2), i.e., 45 per cent marks, may I know, Sir, how the Government will deal with that ?

SHRI P. GOVINDA MENON : With respect to pre-matric matters, my information is, subject to correction—if I made a mistake it is with respect to the several States—that tuition is free and, therefore, this question does not arise. This question is with respect to post-matric scholarships and other things.

SHRI K. S. CHAVDA : My question relates to pre-matric scholarships and not free tuition.

SHRI P. GOVINDA MENON : Other amounts are also given in some other States I know of.

SHRI KESAVAN (THAZHAVA) (Kerala) : The Budget allotment for this purpose is not sufficient to meet the expenses. May I know from the hon. Minister whether he has already made any demands for higher amounts and, if not, may I know whether he would be making a demand for higher amounts to meet the expenditure?

SHRI P. GOVINDA MENON : I am satisfied that the post-matric scholarships now being given, particularly to students

in technical institutions, are not sufficient and, therefore, I have raised the question of enhancing the quantum of post-matric scholarships and the matter is pending with the Finance Ministry.

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) : I should like to know from that Minister whether this order was given at the instance of the Ministers or it was done by some officers of the Ministry. It only shows the attitude of those who are administering the Social Welfare Department. I would like to know whether it was a ministerial decision. Another thing I would like to know. In view of the fact that a Parliamentary Committee is already possessed of these issues, why was this kind of order issued at all, when it is already going into these matters? I would like to know also whether it is not proper that we should consider increasing these grants to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, instead of trying to curtail it or trying to adjust whatever we want to do within the funds available. It only shows the attitude of the persons administering it. I should like to know whether it was done at the level of the Ministers or at the level of the officers. If it was done at the level of the officers, I would like to suggest to the Minister that he should have such officers who have a proper attitude towards this kind of things.

SHRI P. GOVINDA MENON : This matter is being considered and I agree with him that an enhancement is necessary. As regards the order I take full responsibility for the order.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जिस आर्डर पर आज हमारे सदन में एतराज हो रहा है उस पर मंत्री महोदय ने स्वयं कभी विचार किया है क्या । जिन हरिजन और गिरिजन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल रही है उनको सहायता प्राप्त करने से रोकने के लिये ही उनके विभाग के लोगों ने ऐसा आर्डर दे कर के ऐसा किया । इसका सबूत दो बातों से प्रमाणित हो जाता है । एक तो यह है कि उन पोस्ट ग्रेज्युएट स्टूडेंट्स को स्कालरशिप मिलेगा जिन को परीक्षा में 45 प्रति शत अंक प्राप्त हों । आप दिल्ली युनिवर्सिटी को छोड़ दीजिये । बाकी प्रदेशों में एक एक युनिवर्सिटी में जो बी०ए०

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

पास करने वाले लड़कों को मार्क्स मिलने हैं उनको आप देखिये । वहां पर आप देखेंगे कि जनरली जो और स्टूडेंट्स हैं और जिन के मार्क्स 45 परसेंट से ऊपर हैं उनकी संख्या बहुत कम है । हरिजन स्टूडेंट तो कोई बिरला ही होगा जिस के मार्क्स 45 परसेंट से ऊपर होंगे । इससे प्रतीत है कि ऐसा इस लिये किया गया है जिस से किसी हरिजन या गिरीजन विद्यार्थी को स्कालरशिप मिले । दूसर राज्य सरकारों की ओर से हरिजन और अन्य दूसरे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के नीचे स्कालरशिप दिया जाता है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की ओर से सारे स्कूलों को लिख दिया गया कि हरिजन विद्यार्थियों की पढाई फ्री कर दी जाय और उनको जो खर्चा पड़ेगा वह राज्य सरकारें वहन करेंगी । और दूसरी सरकारों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहां तक बिहार सरकार का प्रश्न है मेरी यह निजी जानकारी है कि वहां जिन स्कूलों ने हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा को फ्री किया उनका पेमेंट सरकार की ओर से नहीं हुआ और उसके कारण बहुत स्कूल वालों को कहना पड़ा कि हम हरिजनों को फ्री पढाने में असमर्थ हैं । तो मेरा यह चार्ज है सरकार पर कि सरकार की यह चाल है और सरकार ने जान बूझ कर ...

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : चाल तो है, लेकिन आप का क्वेश्चन क्या है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वही क्वेश्चन है कि इस षडयंत्र पर स्वयं मंत्री जी ने विचार किया या नहीं या जो विभाग से सूचना आ गई उसी के अनुसार उन्होंने उत्तर दे दिया ।

SHRI P. GOVINDA MENON : Mr. Vice-Chairman, Sir, *prima facie* I thought that the three points in the order would be considered to be acceptable. For example when I said that a person who is above the age of thirty years should not be entering any post-matric course for the first time and claim a scholarship, I thought there is nothing wrong in it.

SHRI GODEY MURAHARI : Why? Most of them may be of thirty years.

SHRI P. GOVINDA MENON : That is why I used the words '*prima facie*' Regarding the means test, I thought that there would be no objection if persons, whose parents earn a certain income above a certain level, are not getting post-matric scholarships. I thought it would be giving an advantage to those who are placed in such a fortunate circumstance. Regarding the merit test of 45 per cent, Members here say that very few students belonging to this community get more than 45 per cent and I accept it and if that is so, that portion of the order is wrong. In any event after this order was issued the Committee about which I spoke earlier has taken notice of it and is considering it, and I again repeat that I would await their proposal.

श्री गणेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश) : अब तक प्रिमेट्रिक एज्यूकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि वह उसको कन्टीन्यू कर सके । तो क्या माननीय मंत्री जो इस बात पर विचार करेंगे कि प्रिमेट्रिक एज्यूकेशन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले ?

SHRI P. GOVINDA MENON : That is a new question of policy which does not arise from this. I would like to have time to consider it.

श्री बी० एन० मंडल (बिहार) : क्या यह बात सही है कि जो आर्डर सरकार का निकला आदिवासी स्टूडेंट्स के बारे में इसको लेकर कोई बहुत बड़ा आन्दोलन मनीषूर में खड़ा हुआ है और कलही स्टूडेंट्स जो इसके लिए डिमांड-स्ट्रेशन कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे, उनको लाटियों से पीटा गया है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Have you any information ?

SHRI P. GOVINDA MENON : I have no information.

SHRI BHUPESH GUPTA : He should have this information. It is in the Hindustan Standard again dated 30th July. Anyway, first of all it remains to be explained how this order or regulation came to be issued so light-heartedly. Now he says it is under consideration of the Committee of Parliament. May I know why leading members of the Scheduled Caste community were not consulted by the

Minister before issuing this kind of order? secondly, I should like to know whether we have an assurance that this order would be forthwith withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : He has stated.

SHRI BHUPESH GUPTA : It should be done. Now it is surprising. On the one hand we see in the paper that the Cabinet has decided to extend the period of safeguards by another ten years, and rightly so, as far as Scheduled Castes are concerned. At the same time we find that they are issuing such an order despite the recommendation of the Committee on Untouchability which has a devastating findings against the manner in which the constitutional obligations are being implemented. The position is this. Here it is not a question of marks and other things. Here it is a question of helping the members belonging to the Scheduled Caste and backward communities to come up, of giving them extra assistance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : He has explained the position.

SHRI BHUPESH GUPTA : He has explained nothing. It may be a few lakhs or a crore of rupees. The Perumal Committee has pointed out that the money sanctioned by the Government is not even spent by the various Departments and Ministries, meant for the welfare of the Scheduled Castes and backward communities. You will be surprised the Perumal Committee says that despite the Untouchability Law only 1000 prosecutions have been obtained ever since the Untouchability Law came into being.

Now take the case of Civil Service. How many Scheduled Caste people have got employment here? Somehow or other a situation is created by which they do not get their due share, do not get the promotions they deserve, and always there is a back-log.

I should therefore like to make the following suggestion that the hon. Minister should immediately convene a meeting of all leaders belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and discuss the matter on the basis of the joint letter which they have submitted to the Prime Minister dated the 30th July on this very subject, and related subjects should be discussed. Since the Minister said that

he is personally responsible, I am not going to blame any officer at the moment because I am concerned with the Minister here, but surely the decision has been taken with a bureaucratic outlook; humane outlook is not seen in that order. It is an administrative, cruel, soulless order which disregards the realities of our life and the anguish of millions and millions of the people belonging to the Scheduled Castes and backward communities. I therefore demand that a meeting of the leading members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes readily available in Parliament be immediately called by the hon. Minister and the whole thing be thrashed out. What is more, the entire responsibility must be borne by the Centre and it is no use passing it on to the States. The constitutional obligations must be carried out with a view to promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward communities, and the Centre not only must find the money but it must at the same time, in consultation with the accredited representatives of those communities, formulate a correct policy and set up a proper machinery for the implementation of such policy.

SHRI P. GOVINDA MENON : The only statement which the hon. Member made about this matter was that it was a light-hearted order. I do not think so. It was a considered order. But in deference to the opinion expressed in the House I am staying it.

PAPERS LAID ON THE TABLE

THIRTY-SIXTH ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1967-68) OF THE INDIAN STATISTICAL INSTITUTE, CALCUTTA

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI JAISUKHLAL HATHI) : Sir, on behalf of Shrimati Indira Gandhi, I beg to lay on the Table a copy of the Thirty-sixth Annual Report and Accounts of the Indian Statistical Institute, Calcutta, for the year 1967-68, together with the Auditors' Report on the Accounts. [Placed in Library. See No. LT-1431/69.]

LETTER FROM THE PRESIDENT OF PAKISTAN

SHRI JAISUKHLAL HATHI : Sir, on behalf of Shri Dinesh Singh, I also lay on the Table a copy of letter dated July 26, 1969, from General Agha Muhammad Yahya Khan, President of Pakistan, to the Prime Minister of India. [Placed in Library. See No. LT-1515/69.]